

## From Page One

## एससीओ प्रमुखों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की

श्री शी जिनपिंग, जो अक्सर अमेरिकी टैरिफ पर अनिश्चितताओं के लिए "शीत युद्ध मानसिकता" शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं, ने कहा, "शीत युद्ध की मानसिकता और धौंस-धमकी की परछाइयाँ कम नहीं हो रही हैं, और नई चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं।"

शिखर सम्मेलन में घोषणापत्र, जो व्यापार में वैश्विक अनिश्चितताओं और "अस्थिर और अराजक वैश्विक स्थिति" के बीच वैश्विक दक्षिण को मज़बूत करने पर केंद्रित था, की शुरुआत इस कथन के साथ हुई कि दुनिया "ऐसे गंभीर ऐतिहासिक परिवर्तनों से गुज़र रही है जो राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं"। सोमवार दोपहर 'एससीओप्लस' बैठक की अध्यक्षता करने वाले श्री शी जिनपिंग ने एक वैश्विक शासन पहल (जीजीआई) का प्रस्ताव रखा, जिसमें देशों से एक अधिक न्यायसंगत और समतापूर्ण वैश्विक शासन प्रणाली के लिए मिलकर काम करने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन का पालन करने, बहुपक्षवाद का पालन करने, जनकेंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करने और वास्तविक कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार रातशिखर सम्मेलन के बाद कहा कि जीजीआई का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करना और देशों को बहुपक्षीय तंत्रों पर भरोसा करके वैश्विक शासन प्रणाली के सुधार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान और आर्मेनिया ने शिखर सम्मेलन में राजनयिक संबंध विकसित करने की घोषणा की है।

श्री वांग ने घोषणा की कि समूह ने गैर-सदस्य देशों - संवाद भागीदार और पर्यवेक्षक - को दिए गए दर्जे को एकल भागीदार के रूप में विलय करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि लाओस को एससीओ के एक भागीदार देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जिससे समूह की कुल संख्या 10 सदस्यों और 17 भागीदारों के साथ 27 हो गई है। एससीओ के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव ने कहा कि एससीओ विकास बैंक की स्थापना पर सहमति बनी है, जो बीजिंग की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा है।

गाजा पर इज़राइल के चल रहे युद्ध और गाजा पट्टी में व्याप्त भयावह मानवीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी सदस्य देशों ने "गहरी चिंता" व्यक्त की और इस क्षेत्र में "ऐसी कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की जिनके कारण बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं"। घोषणापत्र में कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी मुद्दे का 'व्यापक और न्यायसंगत समाधान" ही पश्चिम एशिया में शांति सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है।

भारत ने भी समूह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर जून में ईरान, जो एक सदस्य देश है, के विरुद्ध इज़राइल और अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की, जिसमें तेहरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 के महत्व की पुनः पुष्टि की, जिसमें ईरान पर उसकेपरमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गएप्रतिबंधों को हटाने के प्रावधान शामिल थे।

घोषणापत्र में अफ़ग़ानिस्तान की राजनीतिक स्थिति का भी उल्लेख किया गया, जिसे समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वह शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। सदस्यों ने दोहराया कि समाज के "सभी जातीय-राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी वाली एक समावेशी सरकार" का गठन ही अफ़ग़ानिस्तान में स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है।

भारत को छोड़कर सभी सदस्य देशों ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रति अपने समर्थन की भी पुष्टि की। श्री शी ने अपने उद्घाटन भाषण में, इस वर्ष के भीतर सदस्य देशों को 2 अरब येन का अनुदान और अगले तीन वर्षों में एससीओ इंटरबैंक कंसोर्टियम के सदस्य बैंकों को अतिरिक्त 10 अरब येन का ऋण प्रदान करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि समूह को जल्द से जल्द एक "एससीओ विकास बैंक" स्थापित करना चाहिए।

घोषणा में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का भी स्वागत किया गया जिसमें "नाज़ीवाद, नव-नाज़ीवाद और अन्य प्रथाओं के महिमामंडन का विरोध करने" का आह्वान किया गया था जो नस्लवाद, ज़ेनोफोबिया और संबंधित असाहिष्णुता के समकालीन रूपों को बढ़ाने में योगदान करते हैं।

*(सुहासिनी हैदर के इनपुट सहित)*

*विप्रेक्ष पी. वेंकटेश, चाइना पब्लिक डिलोमेसी एसोसिएशन के निमंत्रण पर चीन में है।*

## ‘SAR ने नामांकन की अंतिम तिथि तक स्वागत का दावा किया’

न्यायालय ने पहले ही चुनावप्राधिकरण को मतदाता सूचीमें नाम शामिल कराने के इच्छुक लोगों से आधार या सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार करने का निर्देश दिया था।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि एसआईआर के पैरा 12(ए)(ii) में नामांकन की अंतिम तिथि तक किसी भी नाम को शामिल या हटाने का प्रावधान है।

सोमवार को जारी चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, नामों को पुनः शामिल करने के लिए लगभग 37,000 आवेदन और नाम हटाने के लिए 2,17,000 आवेदन दायर किए गए हैं। कुल 16,56,886 नए मतदाता, जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि मसौदा मतदाता सूचीमें शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने पत्रता दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूचीमें लगभग 7.24 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है - जो जुलाई 2025 की पिछली सूची की तुलना में 65 लाख कम है।

चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा दायर ज्यादातर दावे और आपत्तियाँ मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए थीं, न कि उन्हें शामिल करने के लिए।

चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते से उन मतदाताओंको नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है जिनके दस्तावेज अधूरे थे, और लगभग 3 लाख ऐसे दस्तावेज पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

एसआईआर के आदेश के अनुसार, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) को सभी दलों की जाँच करने, स्वंप्रणया से जाँच करने और किसी भी मतदाता को नोटिस जारी करने का अधिकार है।

यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटा दिया जाता है, तो ईआरओ इसके कारणों को बताते हुए एक "स्पीकिंग ऑर्डर" जारी करेगा।

स्पीकिंग ऑर्डर वह होता है जिसमें प्राधिकारी अपने निर्णय के पीछे के कारणों को स्पष्ट रूप से बताता है, और उसे सक्षमों, तथ्यों और लागू कानूनों से जोड़ता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय मनमाना न हो और ठोस तर्कों को दर्शाता हो।

## बिना किसी अनुवाद गलती वाला संस्करण फ्री में पढ़ने के लिए अभी 8168305050 पर संपर्क करें।

## भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को सहायता प्रदान की

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

भारत ने सोमवार को अफ़ग़ानिस्तान के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजना शुरू कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और कहा कि भारत अफ़ग़ानिस्तान को "हर संभव मानवीय सहायता" प्रदान करेगा। श्री मोदी ने एक संदेश में कहा, "इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएँ शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"

इससे पहले, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तालिबान प्रशासन के 'विदेश मंत्री' आमिर खान मुताकी से बात की। उन्होंने कहा, "बताया कि भारत ने आज काबुल में 1,000 परिवारों के लिए तंबू पहुँचाए हैं। भारतीय मिशन द्वारा काबुल से कुनार तक 15 टन खद्यो सामग्री भी तुरंत पहुँचाई जा रही है। कल से भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी।"

# भारत ने टैरिफ शून्य करने की पेशकश की है, लेकिन इसमें देर हो रही है: डोनाल्ड ट्रंप

**Sriram Lakshman**

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावाकिया कि भारत ने टैरिफ को शून्य करने की पेशकश की थी। उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को "एकतरफ़ा आपदा" बताते हुए यह संकेत दिया कि यह कथित पेशकश बहुत देर से आई है।

श्री ट्रंप का सोशल मीडिया साइट ट्रथ सोशल पर यह पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन केतियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद आया।

श्री ट्रंप ने लिखा, "उन्होंने [भारत ने] अब अपने टैरिफ को शून्य करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था।"



Donald Trump

उन्होंने लिखा, "अब तक यह पूरी तरह से एकतरफ़ा रिश्ता रहा है, और यह कई दशकों से ऐसा ही रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत ने अब तक हम पर किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा टैरिफ़ लगाए हैं, जिससे हमारे व्यवसाय भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं। यह पूरी तरह से एकतरफ़ा आपदा रही है।"

श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अपना ज्यादातर तेल और सैन्य उपकरण रूस से खरीदता है, और अमेरिका से बहुत कम।

श्री ट्रम्प और श्री मोदी के बीच स्पष्ट मित्रता - जो पहले ट्रम्प प्रशासन में स्पष्ट थी - हाल के हफ़्तों में अमेरिका को भारतीय निर्यात पर लागू असाधारण 50% डिफ़ॉल्ट टैरिफ दर और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर पहुँचने में असमर्थता के कारण बिखर गई है। इस टैरिफ में रूस के साथ भारत के हथियार और ऊर्जा व्यापार पर लगाया गया 25% शुल्क भी शामिल है।

इससे ठीक पहले, नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने अमेरिका-भारत संबंधों को आशावादी शब्दों में प्रस्तुत किया था। एक्स पर एक पोस्ट में, दूतावास ने कहा था कि यह संबंध "नई ऊँचाइयों को छू रहा है"। इसने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के हवाले से कहा कि लोगों के बीच आपसी संबंधों की प्रशंसा भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

**'ब्राह्मण मुनाफ़ाखोरी'** व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने रविवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि भारत "क्रैमलिन के लिए एक धोबीघर" है।

"मोदी एक महान नेता हैं। मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद, वे पुतिन और [चीनी राष्ट्रपति] शी जिनपिंग के साथ क्यों घुल-मिल रहे हैं," श्री नवारो ने कहा।

"तो मैं बस इतना कहूँगा कि भारत के लोग, कृपया समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफ़ा कमा रहे हैं," उन्होंने आगे कहा। यह स्पष्ट नहीं है कि श्री नवारो 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग शाब्दिक रूप से कर रहे थे या अभिजात वर्ग के संदर्भ में।